# न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

**(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)**

**प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 04/2015**

**दायर दिनांक : 30.07.2015**

**आदेश दिनांक : 28.11.2019**

**—:अनवान:—**

सवाईसिंह पिता गोपालसिंह राठौड निवासी शंकरपुरा तहसील व जिला राजसमन्द मृतक के बजाय वारिस

1. श्री देवेन्द्रसिंह पिता स्व0 श्री सवाईसिंह राठौड राजपूत उम्र 58 वर्ष निवासी शंकरपुरा तहसील व जिला राजसमन्द

—प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार राजसमन्द

—अप्रार्थीगण

**<u>क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997</u>**

**उपस्थित:—**

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 व 02
3. श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02
4. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 13.04.2015 को पारित एवार्ड राजस्व ग्राम शंकरपुरा में स्थित आराजी नम्बर 30/1, 30/2 की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में चुनौती दी गई है तथा एवार्ड अभिवृद्धि के लिये विभिन्न आधार अपने प्रार्थनापत्र में लिये।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा नियमानुसार तत्समय प्रचलित डी.एल.सी. दर से मुआवजा तय किया गया है। प्रार्थी वर्तमान बाजार दर से मुआवजा चाहता है जो स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी को भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा की कार्यवाही विचाराधीन हैं। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं एवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा उक्त एवार्ड अभिवृद्धि के लिये प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मुआवजा राशि प्रार्थी को डीएलसी दर अनुसार भुगतान नहीं की गयी है तथा उक्त भूमि प्रार्थी की वाणिज्यिक उपयोग की होते हुए भी प्रार्थी को मुआवजा राशि वाणिज्यिक दर से भुगतान जारी नहीं किया गया है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि है लेकिन नगर परिषद की सीमा में होने से विक्रयपत्र के पंजीयन के समय 3 गुणा दर कृषि भूमि की मानते हुए पंजीयन किया जाता है तथा 20 फीट तक वाणिज्यिक मानते हुए पंजीयन शुल्क प्राप्त किया जाता है। भूमि के एवार्ड के संबंध में देरी का ब्याज एवं तोषण राशि भी अदा नहीं की गयी। यह भी निवेदन किया कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत उक्त मामले में दिनांक 01.01.2015 से लागू हो चुके हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मानसिंह बनाम भारत संघ के मामले में 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिये जाने के निर्देश/आदेश इसी से लगी हुई भूमि के संबंध में प्रदान किये गयें हैं लेकिन प्रार्थी को मुआवजा राशि वाणिज्यिक दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत भुगतान नहीं की गयी है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावे।

विपक्षी द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी को डीएलसी दर पर ही भूमि का मुआवजा अदा किया गया है तथा प्रार्थी की भूमि अवाप्ति के समय जो किस्म रेकर्ड में दर्ज थी,उसी अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। प्रार्थी ने कोई आपत्ति एवं क्लेम आवेदन मुआवजा के संबंध में पेश नहीं किया है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं। मुआवजा का निर्धारण विधिनुसार सही किया गया है। गणना में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। प्रार्थी की याचिका आधारहीन है अतः खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा कृषि भूमि की दर से तय किया गया है जबकि उक्त भूमि के आस–पास में वाणिज्यिक रूपान्तरणशुदा होकर नगरपालिका द्वारा वाणिज्यिक रूपान्तरण का पट्टे जारी किये गये है। इसलिए प्रार्थी को वाणिज्यिक दर से मुआवजा का भुगतान किया गया । साथ ही यह भी निवेदन किया है कि इसी आराजी में वाणिज्यिक रूपान्तरणशुदा भूमि होकर पट्टे नगरपालिका द्वारा जारी किये गये है। जो एक ही जमीन है। इसलिए कृषि भूमि की दर से तय किया गया मुआवजा गलत है। प्रार्थी के मामले में वाणिज्यिक दर तय होती है। साथ ही भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से लागू हो चुके है। जिसके संबंध में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मानसिंह बनाम भारत संघ के मामले में एवं इसी अवार्ड में वर्णित खातेदार केशरसिंह व कमला की आराजी के संबंध में भी भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत भुगतान किये जाने के आदेश जारी किये गये है। विपक्षी ओर से मौखिक तर्क रहा है कि प्रार्थी की भूमि कृषि भूमि होकर राजस्व रेकार्ड मे कृषि भूमि है। जिसके अनुसार ही कृषि भूमि की डी0एल0सी0 अनुसार अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी वाणिज्यिक दर से अवार्ड प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की पालना की जा रही है। संशोधन अवार्ड जारी किया गया है। जिसकी भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अवार्ड वृद्धि हेतु दो आधार लिये गये है। जिसमें अवार्ड कृषि भूमि की दर के स्थान पर वाणिज्यिक दर एवं भुमि अर्जन अधिनियम 2013 के आधार पर मुआवजा राशि का भुगतान करने बाबत आधार लिये गये है। इस संबंध मे विपक्षी द्वारा प्रार्थी को कृषि भूमि की दर से मुआवजा राशि भुगतान की गयी है। प्रार्थी की भूमि कृषि भूमि मुआवजा राशि अधिसूचना 3ए दिनांक को प्रचलित भूमि की दर अनुसार देय होती है। प्रार्थी की भूमि अधिसूचना के दिनांक किस्म कृषि भूमि होने से कृषि भूमि की दर से ही प्रार्थी भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसमें विपक्षी द्वारा कृषि भूमि की दर से भुगतान किये जाने मे कोई त्रुटी नहीं पायी जाती है। जहां तक भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा राशि का भुगतान का प्रश्न है विपक्षी स्वयं ने स्वीकार किया है वह भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत संशोधित अवार्ड जारी किया जा चुका है तथा इसके भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त परिस्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विपक्षी सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी/अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द प्रतिप्रेषित इस निर्देश के साथ किया जाता है कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत एवं जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा निर्धारित दर जोन अनुसार स्थित भूमि का संशोधित अवार्ड जारी कर शीघ्र भुगतान किया जावें।

आदेश की एक प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावे।

**(अरविन्द कुमार पोसवाल)**
**मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर**
**राजसमंद**

आदेश आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(अरविन्द कुमार पोसवाल)**
**मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर**
**राजसमंद**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)